

बड़ी फूड कंपनियों के आगे झुक गई सरकार

हेल्थ संबंधित चेतावनी पर यू-टर्न, सुप्रीम कोर्ट नाराज

■ दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क. सोचिए आप बाजार से जो चिप्स या सॉफ्ट ड्रिंक खरीद रहे हैं, उस पर अगर बड़े-बड़े संकेतों में बताया गया हो कि इसमें कितना फैट है और कितनी शुगर है, तो कैसा रहेगा? जाहिर है कि शायद ग्राहकों को खरीदने से पहले ही पता लग जाएगा कि वह चीज उनके लिए कितनी हानिकारक है. भारत में कुछ ऐसा ही होने जा रहा था, लेकिन बड़ी कंपनियों के दबाव में सरकार इस नियम को लागू करने से पहले ही झुकती नजर आ रही है. दरअसल भारत में पैकेज्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक की पैकेजिंग पर चीनी, नमक और फैट की अधिक मात्रा को लेकर सामने से स्पष्ट चेतावनी देने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक ने फूड इंस्ट्रुमेंट के विरोध के बाद पैकेज के सामने रंगीन चेतावनी लेबल लगाने की अपनी योजना से पीछे हट गया. मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.



भारत में फैंटा में तीन गुना ज्यादा चीनी

रिपोर्ट में भारत और ब्रिटेन में बिकने वाले फैंटा की तुलना की गई है. ब्रिटेन में बिकने वाले एक केन फैंटा में करीब 63 कैलोरी बताई गई हैं, जबकि भारत में उसी ब्रांड के पेय में करीब तीन गुना ज्यादा चीनी होने का दावा किया गया है. भारत में इसके अलावा एक आर्टिफिशियल कलर का भी इस्तेमाल होता है. यूरोप में कुछ खाद्य उत्पादों में ऐसे रंगों की मौजूदगी पर प्रमुख स्वास्थ्य चेतावनी की जरूरत होती है, जबकि भारत में इसकी जानकारी पैकेज के पीछे छुपे अक्षरों में दी जाती है. यह अंतर भारत में पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों के लेबलिंग नियमों को लेकर चल रही बहस को और गंभीर बनाता है.

सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यकर्ताओं ने नियामक के फैसले को चुनौती दी है. उनका कहना है कि पैकेज्ड फूड में मौजूद ज्यादा चीनी, नमक और फैट के बारे में ग्राहकों को आसानी से समझ आने वाली जानकारी मिलनी चाहिए.

क्या चाहते थे भारतीय नियामक

- भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई पिछले कई वर्षों से पैकेज्ड फूड के सामने पोषण संबंधी चेतावनी देने के अलग-अलग विकल्पों पर विचार करता रहा है.
- इनमें रंगों के जरिए यह बताना शामिल था कि किसी उत्पाद में चीनी, नमक या फैट की मात्रा ज्यादा है. उदाहरण के लिए ज्यादा चीनी या नमक के लिए लाल संकेत और कम फैट जैसी जानकारी के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जा सकता था.
- ऐसे फ्रंट-ऑफ-पैक लेबल करीब 20 देशों में अलग-अलग रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्राहक बिना पैकेट के पीछे लिखी लंबी जानकारी पढ़े भी किसी उत्पाद की पोषण संबंधी स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल को लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. फरवरी में कोर्ट ने नियामक को चेतावनी लेबल की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया था और इंजराइन के लाल-हरे लेबल सिस्टम का भी अध्ययन करने को कहा था. हालांकि मार्च की डेडलाई बैठक के बाद एफएसएसआई ने अगस्त में कोर्ट को बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पैकेजिंग नियम बनाना मुश्किल है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नियामक को फटकार लगाते हुए कहा कि दुनिया यह पता होना चाहिए कि भारत अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है.

बड़ी कंपनियों ने किया विरोध

- रॉयटर्स के मुताबिक 19 मार्च को एफएसएसआई और फूड इंस्ट्रुमेंट के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कंपनियों ने प्रस्तावित चेतावनी लेबल पर सवाल उठाए थे.
- बैठक की रिकॉर्डिंग के अनुसार कोका कोला इंडिया की वरिष्ठ अधिकारी मिली भट्टाचार्य ने कहा कि केवल किसी प्रतीक या आइकन को देखकर ग्राहक अपनी डाइट में बड़ा बदलाव नहीं करेगा.
- फूड इंस्ट्रुमेंट ने चेतावनी लेबल को भ्रम पैदा करने वाला और प्रभावी नहीं होने वाला भी बताया.
- कंपनियों की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि नियामकों को चेतावनी लेबल की बजाय लोगों को खाने की मात्रा पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
- रिपोर्ट के मुताबिक कोका-कोला की कुछ यूरोपीय बाजारों में बिकने वाली ड्रिंक्स पर कंपनी ने खुद टैफिक लाइट जैसे लेबल इस्तेमाल किए हैं.
- कोका-कोला एचबीसी अपनी वेबसाइट पर ऐसे लेबल को ग्राहकों को स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी देने वाला बताती है.

नेस्ले पर भी उठे सवाल

नेस्ले भी भारत में फूड लेबलिंग से जुड़े इंडस्ट्री समूहों का हिस्सा रही है. जिन्होंने नियामक के पुराने प्रस्तावों का विरोध किया था. दूसरी ओर कंपनी ब्रिटेन में 2013 से कुछ उत्पादों पर पोषण संबंधी इंटरैक्टिव लेबल का इस्तेमाल करती रही है. भारत और दूसरे देशों में एक ही ब्रांड के उत्पादों की सामग्री में अंतर को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं.

तैयारी : सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव हर पायलट का साल में एक बार होगा डोप टेस्ट

■ दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क. केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार सभी पायलट के लिए वार्षिक डोप टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. मौजूदा समय में पूरे नेटवर्क पर केवल 10 प्रतिशत पायलट का वार्षिक डोप टेस्ट करना अनिवार्य है. नायडू ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सभी पक्षकारों से हर पायलट का साल में एक बार डोप टेस्ट कराने पर विचार कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि रेगुलेटर कोई अंतिम फैसला लेने से पहले टेस्टिंग के दायरे को बढ़ाने से होने वाले सुरक्षा संबंधी फायदों और कामकाज पर पड़ने वाले असर की जांच कर रहा है. एयर इंडिया की घटना के बाद आया फैसला : यह प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत में एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान की घटना के बाद पायलटों के लिए नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से जुड़े नियमों की कड़ी जांच के बीच आया है. नायडू ने कहा कि नियमों को मजबूत करने पर बातचीत और घटना की चल रही जांच से अलग की जा रही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा



पायलट का टेस्ट पॉजिटिव

इस घटना के बाद चित्ताएं तब और बढ़ गईं जब पायलट-इन-कमांड का कन्फर्मेटरी ड्रग टेस्ट मॉरिजुआना के लिए पॉजिटिव आया. इसके बाद एयर इंडिया ने अपने सभी पायलटों के लिए ड्रग स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ा दिया. बाद में दो और पायलट शुरुआती ड्रग टेस्ट में फेल पाए गए और कन्फर्मेटरी टेस्ट के नतीजों का इंतजार करते हुए हवेलियात के तीर पर उन्हें प्लाइट ड्यूटी से हटा दिया गया.

कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) एयर इंडिया की घटना के सिलसिले में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और विमान के दूसरे सिस्टम की जांच कर रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही एक शुरुआती रिपोर्ट जारी की जा सकती है.

# शेयर	MARKET
बीएसई	77,656.09 (▲ 286.98)
निफ्टी	24,334.55 (▲ 115.50)
निफ्टी IT	30,771.80 (▲ 174.90)
₹ \$	95.46 (प्रति डॉलर)
सोना स्टैंडर्ड (10 ग्राम)	चांदी (प्रति किग्रा)
नागपुर 1,63,000 (▼)	2,44,500 (▼)
मुंबई 1,62,800 (▼)	2,43,500 (▼)
कच्चा तेल	89.32 (\$ प्रति बैरल)

अंडा महात्मा फुले मार्केट इटिलिश अंडा 100 नग 510

NEWS विडो

केंद्रीय बोर्ड में तीन नए दिग्गज शामिल

मुंबई. केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में तीन नए अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किए हैं. इन नियुक्तियों में पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन, पूर्व नौकरशाह एनी जॉर्ज मैथ्यू और परामर्श फर्म बीसीजी इंडिया के अध्यक्ष जनमेजय कुमार सिन्हा शामिल हैं. ये सभी 24 अगस्त, 2026 से चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक पद पर रहेंगे.

100 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग

मुंबई. कोटक महिंद्र बैंक ने प्रारंभिक राजस्व चरण के स्टार्टअप्स के लिए अपनी प्रमुख सीएसआर पहल कोटक बिजलैक्स एक्सप्लेरेटर प्रोग्राम के सीजन 3 की घोषणा की. सीजन अक्टूबर 2027 तक चलेगा और देशभर के 100 से अधिक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के अवसर और शुरुआती वित्तीय सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान करेगा. सीजन 3 में पांच इनक्यूबेशन पार्टनर शामिल हैं.

1 जीबी मोबाइल डेटा की कीमत 97% घटी

खपत 128 गुना बढ़ी: जियो

■ मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क. देश में पिछले एक दशक में एक जीबी मोबाइल डेटा की कीमत में करीब 97 प्रतिशत की कमी आई है. इसी अवधि में प्रति ग्राहक औसत मासिक वायरलेस डेटा खपत में भी 128 गुना की बढ़ोतरी हुई है. देश की



प्रमुख दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के



मिलाकर कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 243.2 अंक की गिरावट आई थी. वैश्विक बाजार: एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉसी, जापान का निक्की और चीन का शंघाई एएसईई कम्पाजिट सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि हांगकांग का हेंग सेंग मामूली

टंप का 'टैरिफ वार' जारी, चीन के खिलाफ नया प्लान सस्ते सामान पर 7.5% कर संभव

■ दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं. मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, यह कदम चीन पर वैश्विक बाजार में कम कीमत वाले सामान की बाढ़ लाने के आरोप के बाद उठाया जा रहा है. प्रस्तावित शुल्क 7.5 फीसदी हो सकता है, हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ऐसा स्तर तय करना चाहता है जिससे अमेरिका और चीन के बीच चल रहा एक साल का व्यापारिक समझौता प्रभावित न हो. साथ ही सितंबर के अंत में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनिपिंग के बीच प्रस्तावित मुलाकात पर भी इसका असर न पड़े.

चीन पर पहले से लगे शुल्क के ऊपर लगेगा नया टैरिफ

प्रस्तावित नया शुल्क चीन पर पहले से लागू टैरिफ के अतिरिक्त होगा. पिछले महीने अमेरिका ने दुनिया की करीब 60 अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले सामान पर 10 से 12.5 फीसदी तक के शुल्क की घोषणा की थी. इन देशों पर जबर्न मजदूरी से बने उत्पादों पर रोक को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया था. चीन समेत कई देशों ने इस कदम का विरोध किया था. ट्रंप प्रशासन ने मार्च में चीन समेत कई देशों की अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता और जबर्न मजदूरी से जुड़े नियमों को लेकर औपचारिक जांच शुरू की थी.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये आंकड़े साझा करते हुए कहा कि 2016 में एक जीबी मोबाइल डेटा की कीमत औसतन करीब 228 रुपये थी, जो अब घटकर लगभग 7.51 रुपये रह गई है. वहीं इस दौरान डेटा की प्रति व्यक्ति मासिक खपत जो 0.2 जीबी से भी कम थी, दिसंबर 2025 तक 26.7 जीबी पर पहुंच गई है. इसी अवधि में मोबाइल डाउनलोड स्पीड भी 2.5 एम्बीपीएस से बढ़कर 68 एम्बीपीएस से अधिक हो गई है. आर्थिक सार्वजनिक निर्गम लाने की तैयारी कर रही रिलायंस जियो के पांच सितंबर को व्यावसायिक परिचालन के 10 साल पूरे हो जाएंगे.

दो हफ्ते और 40 हजार करोड़ के ऑर्डर मिले



L&T के काम का बजा दुनिया में डंका

■ दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क. भारत की दिग्गज इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने महज दो हफ्तों के भीतर करीब 40,000 करोड़ रुपये के मेगा ऑर्डर हासिल कर बंग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में अपनी धाक बढ़ाई है. हासिल किए गए ऑर्डर की जमा दी है. मिडिल ईस्ट के हाई-वैल्यू हाइड्रोकार्बन व गैस प्रोजेक्ट्स से लेकर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी एनवीडिया के लिए भारत की सबसे बड़ी एआई फेक्ट्रीज बनाने तक-कंपनी को मिले बैंक-टू-बैंक ऑर्डर्स ने इसकी ऑर्डर बुक को रिकॉर्ड मजबूती दी है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर हासिल की

गई इन ऐतिहासिक डीलस ने न केवल वैश्विक पटल पर भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा मनवाया है, बल्कि शेयर बाजार में भी निवेशकों के धरोसे को नए खंख लगा दिए.

सार्वजनिक सूचना

शक्ति क्रेडिट ग्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बीआरएम्पी लॉजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) (सीआईएन: U64990DL1995PT072421) (पंजीकृत कार्यालय: Z-8, होज़े ब्लास, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110016) ईमेल: info@shakticredit.com संपर्क नंबर: 9122121292

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल, सदस्यों और केंद्र सरकार के उचित अनुमोदित के उपरांत तथा कंपनी रजिस्टर, दिल्ली। एंड्रस मान परिवर्तन के पश्चात जारी निगम प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से नया COA (पंजीकरण प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के बाद, बीआरएमपी लॉजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर शक्ति क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कर लिया है।

शक्ति क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के लिए (पूर्व में बीआरएमपी लॉजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) हस्ताक्षर/अंशित फुल्टी बोकर निदेशक दिनांक: 26/08/2026 स्थान: दिल्ली

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

विद्युत सूचना (सर्व एवं निर्माण) भारत-संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उप मुख्य अभियंता (निर्माण-चतुर्थी), उत्तर-पश्चिम रेलवे, डिग्री मार्ग, सेक्टर-11, उदयपुर - 313001 (राजस्थान) निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा प्रपत्र पर ई-निविदा (दो पैकेट प्रणाली) आमंत्रित करते हैं। जो कि दिनांक 14.09.2026 को 15:30 बजे खोली जाएगी। 1. निविदा संख्या : BI-NMTR-09R 2. कार्य का नाम एवं स्थान : उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के अंतर्गत छोटी सादगी होते हुए बाड़ी सादगी - नीमच नई लाइन परियोजना से संबंधित जालोदा जंगीर-नीमच नई लाइन सेक्शन के पूर्णता एवं कमीशनिंग हेतु अतिरिक्त कार्य, जिसमें बैंक/कॉटिंग में मिट्टी का कार्य, ब्लैकोटिंग, सुरक्षा कार्य, ROB/RUB के अग्रोच, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म शेल्डर, स्टेशन भवन, सड़कोटिंग एरिया, नाती, ड्रेनिंग वॉल, स्क्वार्ड संबंधी कार्य तथा अन्य सहायक कार्य शामिल हैं। 3. निविदा का प्रकार : दो पैकेट प्रणाली 4. अनुमानित लागत : राशि 91.91,41,81.63 रुपये 5. ब्याना राशि : राशि 1,83,82,800.00 रुपये 6. कार्य पूर्ण करने की अवधि : (08) माह 7. ई-निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक और समय : दिनांक 14.09.2026 को 15:00 तक 8. वेबसाइट का विवरण : www.iireps.gov.in नोट: कोई भी नैजुल टेंडर स्वीकार नहीं किया जायेगा। 1230-CQ/26

कर्नाटक फूड सेप्टी एंड एड मि नि स्टू यान डिपार्टमेंट ने तीनों कंपनियों के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है. इन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज फूड प्रोडक्ट के तौर पर लिस्ट किए गए गए थे. डिपार्टमेंट ने इन तीनों प्लेटफॉर्म को ऐसी सभी लिस्टिंग और एडवर्टीजमेंट्स को हटाने और धतूरे की फूड के तौर पर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने का निर्देश भी दिया है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

विद्युत सूचना (Tr-D)/खुली निविदा सूचना निविदा सूचना सं. TRD_NAG_TENDER_26-27_24, dated 20.08.2026, कार्य का नाम: नागपुर डिवीजन में स्टेशन, TSS/SP/SSP और सेप्टी बोर्ड आदि के लिए एंक्लाइंग डायग्राम बोर्ड तैयार करना और उनकी सलाई करना, साथ ही सेप्टी पोस्टर और वॉल पेंटिंग का काम। निविदा का मूल्य (रु में): ₹ 71,51,814.00, ब्याना राशि (रु में): ₹ 1,43,000.00

इलेक्ट्रिक ऑफर (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि: 11/09/26 का 15:00 बजे

उपरोक्त टेंडर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.iireps.gov.in देखें। वरि, ईमेल विवरण अभियंता (Tr-D) द.पु.म.रेलवे/नागपुर PAM/39/97 f South East Central Railway X@scrail

दक्षिण मध्य रेलवे हर्षा @SCRailwayindia पर फालो करें। दक्षिण मध्य रेलवे की विविदाओं का विवरण हमारी वेबसाइट www.scr.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

खुली ई-निविदा सूचना संख्या: C/E-29/Elec/M/SC/35/PA/OT/2026-27 दिनांक 28-08-2026

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, अयोध्यावासी नीचे दिए गए कार्य के लिए 24/09/2026 को 15:00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित करते हैं।

क्रमांक: 1, ई-निविदा संख्या: ई-निविदा संख्या C/E-29/Elec/M/SC/35/PA/OT/2026-27, ई-निविदा संख्या: E-M-SC-35-O-T-2026-27 कार्य का नाम: सिंक्रोडराव मंडल विद्युत रखरखाव विभाग - अग्रेष्ठ भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भद्राचलम रोड, महबूबाबाद, मध्या, जंगम, जहरीबाद, मंचिराल, पद्मपल्ली और याददी स्टेशनों पर रंग सहित 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण - विद्युत व्यवस्था। निविदा मूल्य: 62,99,110.12 रुपये, एम्पेडडो: 1,26,000.00 रुपये, सीटीएफ: 0 रुपये, पूर्णता निदेश: 6 महीने.

निविदा की शर्तें/अन्य विवरण IRRPS की वेबसाइट 'www.iireps.gov.in' पर उपलब्ध निविदा दस्तावेजों में उपलब्ध हैं, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे मांग लिया जा सकता है और यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें देखा जा सकता है। निविदा सूचना सिंक्रोडराव मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे, सिंक्रोडराव के वॉरुट डीईई (रखरखाव) के कार्यालय में स्थित नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की गई है, जिसे सभी कार्यवाही करने में देखा जा सकता है।

रेलवे बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता रखरखाव/सिंक्रोडराव। A695

अग्रेष्ठ निविदा शर्तों/विवरणों और टेंडर डकुमेंटेशन डाउनलोड करने के लिए, कृपया वेबसाइट <https://www.iireps.gov.in> या www.scr.indianrailways.gov.in पर जाएं

E-Tender Notice

The Executive Engineer, MSEDCL, Gandhibag Division invites e-Tender in two bid system from experienced reputed agency having experience of similar work in MSEDCL & completing the formalities for Annual Contract for Monthly Meter Reading, Bill printing, Bill Distribution & Acknowledgement receipt of delivery to consumer of All PC O Consumers (IP, Commercial and Others) CT/Whole Current meter Consumers under all Sub-Division's of Gandhibag Division (With CMRI for above 20 KW load consumer & without CMRI for balance Consumers) having Tender No. EE/GBDN/Tech/Re-float/CT-IP Reading/26-27-TT-06. The Tender details are available on website etender.mahadiscom.in/eat/PA/. The Tender documents can be downloaded from aforesaid website from 26.08.2026. Submit the tender duly filled in on or before 11.09.2026 before 17:30 Hrs. NZ / PR No. 125 / 2026 Date : 25.08.2026 Executive Engineer O&M, MSEDCL Gandhibag Division, Nagpur

SRM E-TENDER NOTICE

SRM E-Tenders with the schedule for rates filled in are invited for the following works from reputed agencies in the field preferably from those who have carried out such works in the MSETCL and or registered with State electricity Board, B & C, NTPC, other Govt. / Semi Govt. & Public sector Organizations. The SRM e-tender is to be filled on line and is available on site of Company www.mahatransco.in. Further details are as follows:- SRM E-Tender specification No. EE/EHV/O&M/NGP/Tech/ SRM-E-Tender/26-27/16 (RFX No. 7000041292) towards AMC of Weed Control (9-Cycle), Rodent Control (Monthly) and Trimming/Uprooting of Grass, Weeds, Shrubs & Trees (Twice a Year) at various 220KV & 132KV Sub-Stations under EHV (O&M) Division, MSETCL, Nagpur for estimated cost is Rs. 39,10,275=35 is available on site of Company www.mahatransco.in from dt. 26.08.2026 to 04.09.2026. Last date of submission of offer is 04.09.2026 upto 23.55 Hrs. Opening of Technical bid against the e-tender is dt. 07.09.2026 at 11.00 Hrs. & opening of commercial bid against the same e-tender is dt. 07.09.2026 at 12.00 Hrs. Other terms & condition of the Tender will remain unchanged. For more details please visit www.mahatransco.in.

Sd/- EXECUTIVE ENGINEER EHV (O&M) DIVISION, MSETCL, NAGPUR

Kolhapur Municipal Corporation

Property Tax Department

Tender Notice No. 49 - Extension due to Pre-Bid Meeting

Online bids are invited from eligible bidders for Selection of Agency for Providing Services for Assisting Numbering, Survey, and Assessment of all Properties on Revenue Generation Sharing Basis Model and Providing Required Software and Hardware for Kolhapur Municipal Corporation. The tender document containing the terms and conditions and the response of the Kolhapur Municipal Corporation regarding the objections/queries raised during the Pre-Bid Meeting has been published on the www.mahatenders.gov.in portal. The said tender process has been extended up to 04/09/2026.

Sd/- Commissioner Kolhapur Municipal Corporation